



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469]
No. 469]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 1988/भाद्र 10, 1910
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 1988/BHADRA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिका और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1988

अधिसूचनाएं

सा. का. नि. 896(अ) - केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक
अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा
5 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए तथा भारत सरकार के कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन
मंत्रालय (कामिका तथा प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 27 जून,
1986 की अधिसूचना सा. का. नि.सं. 920 (अ) के त्रम में
उरुनाकुलम की एक स्थान के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट
करती है, जहाँ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठ
पहली सितम्बर, 1988 से सामान्य रूप से कार्य करना शुरू
करेगी।

[संख्या ए - 11019/31/(1)/85 - प्र. अधि.]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training.)

New Delhi, the 1st September, 1988

NOTIFICATIONS

G.S.R. 896 (E) - In exercise of the powers conferred by
sub-section (7) of section 5 of the Administrative Tribunals
Act, 1985 (13 of 1985) and in continuation of the notification
of the Government of India in the Ministry of Personnel,
Public Grievances and Pensions (Department of Personnel
and Training) G.S.R. No. 920-E, dated the 27th June, 1986
the Central Government hereby specifies the Ernakulam as
the place at which the Bench of the Central Administrative
Tribunal shall ordinarily sit with effect from 1st September,
1988.

[No. A-11019/31(1)/85-AT]

सा. का. नि. 897(अ) - प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 13) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कामिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 26 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 610 (अ) में, केन्द्रीय सरकार पहली सितम्बर, 1988 से और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उपर्युक्त अधिसूचना की तालिका के स्थान पर निम्न लिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात्:—

तालिका		
क्र. सं.	न्यायपीठ	न्यायपीठ की अधिकारिता
1	2	3
1.	प्रधान न्यायपीठ (नई दिल्ली)	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र
2.	अहमदाबाद न्यायपीठ	गुजरात राज्य
3.	इलाहाबाद न्यायपीठ	उत्तर प्रदेश राज्य
4.	बंगलौर न्यायपीठ	कर्नाटक राज्य
5.	कलकत्ता न्यायपीठ	सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र।
6.	चण्डीगढ़ न्यायपीठ	जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र।
7.	कटक न्यायपीठ	उड़ीसा राज्य
8.	एर्नाकुलम न्यायपीठ	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र।
9.	गुवाहाटी	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम
10.	हैदराबाद न्यायपीठ	आन्ध्र प्रदेश राज्य
11.	जबलपुर न्यायपीठ	मध्य प्रदेश राज्य
12.	जोधपुर न्यायपीठ	राजस्थान राज्य
13.	मद्रास न्यायपीठ	तमिलनाडु राज्य तथा लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र
14.	न्यू बम्बई न्यायपीठ	महाराष्ट्र तथा गोआ तथा दादर और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र।
15.	पटना न्यायपीठ	बिहार राज्य

[संख्या ए-11019/31(2)/85 - प्र. अति.]
पी. वी. बलसला जी. कुट्टी, अवर सचिव (प्र. अति.)

G.S.R. 897 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes, with effect from 1st September, 1988 the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, and Training Administrative Reforms and Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) G.S.R. No. 610E dated the 26th July, 1985, namely:—

In the said notification, for the Table the following Table shall be substituted, namely:—

TABLE

Sl. No.	Bench	Jurisdiction of the Bench
1.	Principal Bench (New Delhi).	Union territory of Delhi.
2.	Ahmedabad Bench	State of Gujarat
3.	Allahabad Bench	State of Uttar Pradesh
4.	Bangalore Bench	State of Karnataka
5.	Calcutta Bench	State of Sikkim and West Bengal and the Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
6.	Chandigarh Bench	States of Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh and Punjab and the Union territory of Chandigarh.
7.	Cuttack Bench	State of Orissa.
8.	Ernakulam Bench	State of Kerala and the Union territory of Lakshadweep.
9.	Guwahati Bench	States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram.
10.	Hyderabad Bench	State of Andhra Pradesh.
11.	Jabalpur Bench	State of Madhya Pradesh.
12.	Jodhpur Bench	State of Rajasthan.
13.	Madras Bench	State of Tamil Nadu and the Union territory of Pondicherry.
14.	New Bombay Bench	States of Maharashtra, Goa, and the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.
15.	Patna Bench	State of Bihar.

[No. A-110 9/31(2)/85-A.T.]
(MRS.) P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.